द इंफोनिक
एक ई-शासन सूचनापत्र
एनआईसी छत्तीसगढ़

अंक 1 सं. 7

मार्च 2022

कायर आदमी अपनी मौत से पहले न जाने कितनी बार मरता है।
- अज्ञात

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
छत्तीसगढ़ राज्य केंद्र
ए डी - 2 दूसरी मंजिल, कमरा नं. 14,15,16
महानदी भवन , मन्त्रालय,
नवा रायपुर अटलनगर
छत्तीसगढ़ – 492002
https://chhattisgarh.nic.in

समसामयिकी

स्वच्छता पखवाड़ा 2022 एन.आई.सी छत्तीसगढ

एनआईसी छत्तीसगढ़ में 01.02.2022 से 15.02.2022 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। राज्य केन्द्र एवं जिला केन्द्रों के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों ने स्वच्छता प्रतिज्ञा लिया । प्रत्येक दिन के लिए गतिविधियों का एक कार्यक्रम तैयार किया गया था। राज्य केंद्र, जिला इकाइयों और एनआईसी . के सभी अधिकारी और कर्मचारी विभिन्न कार्यालयों के केंद्रों को मेल और संदेशों के माध्यम से सूचित किया गया था| प्रमुख स्थानों पर पोस्टर व बैनर लगाए गए। स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान व्यक्तिगत कार्य क्षेत्र, दीवारें और विभाजन, खिड़कियां और शीशे, फर्नीचर, कंप्यूटर और अन्य उपकरण, सफाई की गई । इस दौरान सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया ।

विदाई समारोह

श्री धीरज कुमार, डी. आई. ओ. बालोद

मा. मो.अकबर जी, मंत्री (परिवहन,आवास एवं पर्यावरण ,वन एवं जलवायु परिवर्तन और विधि विधायी कार्य विभाग) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न हितग्राही मूलक कार्यक्रमों का एन.आई.सी . विडियो कांफ्रेंस के द्वारा आयोजन

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबरद्वारा विधायक निधि से कवर्धा के वार्ड न. 27 सामुदायिक भवन नाहर पार मुक्तिधाम के सामनेसारथी समाज भवन(रु **14.35लाख**) का लोकार्पण

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबरद्वारा **सी.जी.आर.डी.एल.** योजना के तहत जिला कबीरधाम के कवर्धा भोरमदेव मंदिर तक मार्ग उन्नयन कार्य **रु 960.24लाख** का भूमि पूजन कार्यक्रम

उपरोक्त कार्यक्रमों में विभिन जन प्रतिनिधि समाज प्रमुख जिला कबीरधाम के जिलाधीश श्री रमेश कुमार शर्मा एवं सम्बंधित विभागों के अधिकारी / कर्मचारीगण का योगदान रहा| वीडियो कांफ्रेंसिंग के कार्यक्रम हेतु तकनिकी व्यवस्था हेतु जिला सुचना विज्ञान अधिकारी श्री नभ वर्मा एवम नेटवर्क इंजिनियरश्री हिमांशु तिवारी औरश्री विष्णु चंद्रवंशी के माध्यम से सहयोग प्रदान किया गया |

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबरद्वारा जिले केविभिन्न समूहों के 59 लोककलाकारो को सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु **14,15,000 रुपये** की राशि **चेक** के माध्यम से प्रदान किया गया |

मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत 50 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र और 8 हितग्राही को पूर्णता का प्रमाण पत्र वितरण किया गया है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने हितग्राहियों को लाभ दिया। स्वीकृति पत्र का वितरण करते हुए कैबिनेट मंत्री अकबर ने कहा कि योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराना है।

श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन प्रोजेक्ट स्टॉल साइंस कॉलेज ग्राऊंड, जी.ई.रोड, जिला-रायपुर

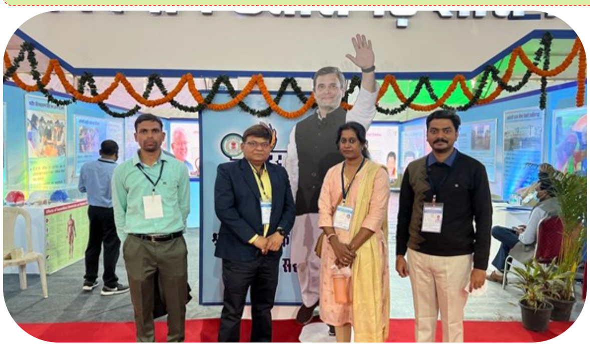

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 03.02.2022 से 06.02.2022 तक साईस कॉलेज ग्राऊंड, जी.ई.रोड, जिला-रायपुर (छ.ग.) में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना एवं गांधी विचार प्रसंग कार्यक्रम रायपुर (छ.ग.) कार्यक्रम आयोजित किया गया था। । उक्त कार्यक्रम में श्रम विभाग की तरफ से स्टॉल लगाया गया था जिसमें श्रम विभाग द्वारा विभिन्न ऑनलाइन योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य, श्रमिक पंजीयन, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा किये जाने वाले कार्य का प्रचार-प्रसार एन.आई.सी. द्वारा किया गया एवं उक्त कार्यक्रम में आने-जाने वाले व्यक्तियों द्वारा विभाग के कार्य से संबंधित पुछे जाने वाले प्रश्नों का जवाब भी दिया गया।

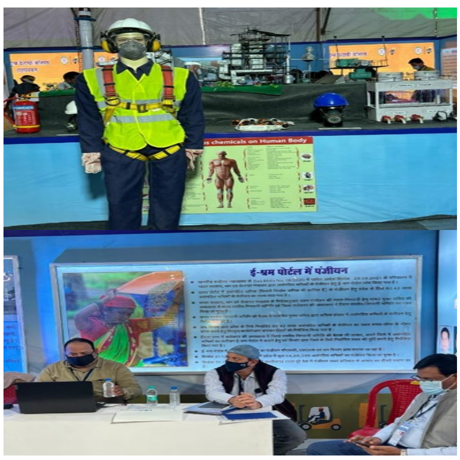

समसामयिकी

जिला प्रशासन द्वारा समय-सीमा प्रकरणों का ऑनलाईन निराकरण का अभिनव पहल

जिला प्रशासन द्वारा समय-सीमा प्रकरणों का ऑनलाईन निराकरण का अभिनव पहल की गई है। कलेक्टर नम्रता गांधी के निर्देशानुसार समय-सीमा में दर्ज आवेदनों को ऑनलाईन करने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी) गरियाबंद द्वारा टी.एल. ऑनलाईन मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी श्री नेहरू निराला ने बताया कि प्रकरणों के ऑनलाईन निराकरण हेतु सभी विभाग प्रमुख को एन.आई.सी द्वारा यूज़र आई.डी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा। जिसके उपयोग से सभी विभाग प्रमुख उनके विभाग से संबंधित दर्ज समय सीमा बैठक के

श्रीमती नम्रता गांधी
आई.ए.एस.
कलेक्टर, गरियाबंद

समय-सीमा पर प्रकरणों के ऑनलाइन निराकरण की शुरु हुई अभिनव पहल

हरिभूमि न्यूज ▸▸ गरियाबंद

जिला प्रशासन ने समय-सीमा प्रकरणों का ऑनलाईन निराकरण का अभिनव पहल की है। कलेक्टर नम्रता गांधी के निर्देशानुसार समय-सीमा में दर्ज आवेदनों को ऑनलाइन करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र गरियाबंद द्वारा टीएल ऑनलाइन मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है। जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी नेहरू निराला ने बताया कि प्रकरणों के ऑनलाइन निराकरण के लिए सभी विभाग प्रमुख को एनआईसी द्वारा यूजर आईडी एवं पासवर्ड

■ टीएल ऑनलाइन मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर का किया निर्माण

उपलब्ध कराया जाएगा। जिसके उपयोग से सभी विभाग प्रमुख उनके विभाग से संबंधित दर्ज समय सीमा बैठक के आवेदनों को देख पायेंगे तथा ऑनलाइन कार्रवाई भी कर सकेंगे। इस सॉफ्टवेयर में यह सुविधा उपलब्ध कराया गया है कि जिन आवेदनों, पत्रों को कलेक्टर द्वारा टीएल मार्क किया जाता है। उन आवेदनों, पत्रों को संबंधित प्रभारी अधिकारी के डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा ऑनलाइन दर्ज किया जाता है। जैसे ही आवेदनों,पत्रों को ऑनलाइन दर्ज करते है वैसे ही संबंधित अधिकारी के टीएल ऑनलाइन ▸▸ शेष पेज 10 पर

आवेदनों को देख पायेंगे तथा ऑनलाईन कार्यवाही भी कर सकेंगे। इस सॉफ्टवेर में यह सुविधा उपलब्ध कराया गया है कि जिन आवेदनों/पत्रों को कलेक्टर द्वारा टीएल मार्क किया जाता है, उन आवेदनों/पत्रों को संबंधित प्रभारी अधिकारी के डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा ऑनलाईन दर्ज किया जाता है। जैसे ही आवेदनों/पत्रों को ऑनलाईन दर्ज करते है वैसे ही संबंधित अधिकारी के टी.एल.ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड पर दिखने लगता है। टी.एल में लंबित पत्रों/आवेदनों पर विभाग प्रमुख के कार्यवाही उपरांत ऑनलाईन निराकरण हेतु कलेक्टर को अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा। कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात संबंधित विभाग प्रमुख के डैशबोर्ड पर लंबित प्रकरण मेनू से हट जायेगा। यह सारी प्रक्रिया ऑनलाईन है जिससे बेहतर रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग किया जायेगा। साथ ही इस सॉफ्टवेयर को रिस्पॉन्सिव डिजाइन किया गया। जिससे सभी यूजर्स इसको आसानी से अपने मोबाइल पर मोबाइल एप्प की तरह इस्तेमाल कर सकेंगें।

नेहरू निराला,
जिला सूचना विज्ञान अधिकारी

प्रशस्ति-पत्र (26 जनवरी 2022)

श्री टेकराम साहू को मुख्य अतिथि श्रीमती ममता चंद्राकर (विधायक पंडरिया) और श्री आशीष छाबड़ा (विधायक, बेमेतरा) द्वारा उनके आधिकारिक कर्तव्यों के प्रति योगदान और समर्पण के लिए 26 जनवरी 2022 (गणतंत्र दिवस) पर प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया गया। वे वर्तमान में जिला सूचना एवं विज्ञान केंद्र बेमेतरा में नेटवर्क इंजिनियर के पद पर कार्यरत हैं| वे रोहित कुमार चंद्रवंशी, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बेमेतरा के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं| उनके आधिकारिक कार्य के प्रति लगन एवं समर्पण को देखते हुये उनका नाम जिला प्रशासन को प्रस्तावित किया था| पिछले दो वर्षों से कोविड -19 महामारी का दौर चल रहा था जिसके कारण से आम सभाएँ, बैठकें, रैली इत्यादि को बंद करने का फैसला लिया गया था। इसके बजाय ऑनलाइन या वर्चुअल मोड के माध्यम से ऑनलाइन बैठक, समीक्षा बैठक, लोकार्पण, भूमि-पूजन इत्यादि होने लगी थी| लॉकडाउन के समय राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला एवं ब्लाक स्तर की प्रतिदिन विभिन्न ऑनलाइन बैठक तथा समीक्षा बैठकें होती थी| उन्होंने ने केन्द्रीय, राज्य, जिला तथा ब्लाक स्तर की वीडियो कांफ्रेंसिंग करने में जिला प्रशासन को तकनीकी सहयोग प्रदान किया था। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, मंत्रियों आदि द्वारा विभिन्न ऑनलाइन उद्घाटन, भूमि पूजन और समीक्षा बैठकों के लिए जिला प्रशासन को सफलतापूर्वक तकनीकी सहयोग दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में सोशल डिस्टेंसींग का पालन करवाना तथा कक्ष को प्रतिदिन सैनीटाईज करवाना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था| इस दौरान उन्होंने इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से प्रबंधित किया।

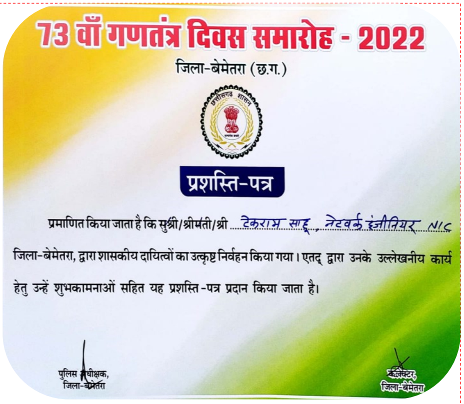

73 वाँ गणतंत्र दिवस समारोह - 2022

जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

प्रशस्ति-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री/श्रीमती/श्री ......टेकराम साहू, नेटवर्क इंजीनियर NIC......

जिला-बेमेतरा, द्वारा शासकीय दायित्वों का उत्कृष्ट निर्वहन किया गया। एतद् द्वारा उनके उल्लेखनीय कार्य हेतु उन्हें शुभकामनाओं सहित यह प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है।

पुलिस अधीक्षक,
जिला-बेमेतरा

कलेक्टर,
जिला-बेमेतरा

छ.ग. महतारी दुलार योजना छ.ग. 2021

लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य शासन के द्वारा राज्य में कोविड-19 करोना के महामारी से मृत व्यक्तियो के बेसहारा/अनाथ बच्चों को नि:शुल्क स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु ''छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना-2021'' लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ निवासी स्कूली शिक्षा पात्रता प्राप्त ऐसे बच्चे जिनके परिवार से कमाने वाले माता या पिता या दोनो की मृत्यु काविड-19 से हुई है और जिनके घर में कमाने वाले वयस्क सदस्य न रहने के कारण भरण-पोषण की समस्या हो गई हो को महतारी दुलार योजना के छात्रवृति दी जाती है। ऐसे पात्र बच्चों को प्रदेश के शासकीय शालाओ में नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध करायी जावेगी। प्रतिभावान छात्रो को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रशिक्षण/कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराया जावेगा। स्कूलो में प्रवेशित छात्रों जो कक्षा 1 से 8 मे अध्यनरत है को रूपये 500 प्रतिमाह और कक्षा 9 से 12 मे अध्यनरत को रूपये 1000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति देय होगा। अशासकीय शालाओं के विद्यार्थियों के शाला शुल्क का भुगतान भी किया जावेगा।

छात्रवृति का वितरण NIC के सहयोग से तैयार छात्रवृति पोर्टल https://schoolscholarship.cg.nic.in/ के माध्यम से DBT(डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के तहत सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में किया जा रहा है। सत्र 2021-22 में शासकिय शालाओ के कुल 2796 विद्यार्थी जिनमे कक्षा 1 से 8 मे अध्यनरत 1583 और कक्षा 9 से 12 मे अध्यनरत 1213 ने और अशासकिय शालाओ के कुल 3208 विद्यार्थी जिनमे कक्षा 1 से 8 मे अध्यनरत 2056 और कक्षा 9 से 12 मे अध्यनरत 1152 ने इस योजना के लिये ऑन-लाइन आवेदन किया था। समस्त पंजीकृत विद्यार्थी मे से 2404 को 4 करोड राशि उनके बैंक खातो मे सीधे जमा की गई।